VISION IAS

www.visionias.in

SUBJECT:	निबंध	Test Code:	1077
Name of Candidate	गौरव कुमार त्रिपाठी		
Medium Hindi/Eng.	हिन्दी	Registration Number	29020
Center	ऑनलाइन	Date	[illegible]

INDEX TABLE

Q. No.	Page No.	Maximum Marks	Marks Obtained

Total Marks Obtained:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. All questions are compulsory.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
3. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
4. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
5. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
6. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

1/8-B, 2nd Floor, Building- Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005

Scanned by CamScanner

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Section A: गुट-निरपेक्षता से बहुनिरपेक्षता तक: भारत की विदेश नीति में परिवर्तन।

"गुट निरपेक्ष देशों के 18वें सम्मेलन में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे।" अखबारों में छपी इस खबर का आम जनमानस से भले ही प्रत्यक्षतः कुछ लेना-देना नहीं था। परंतु विदेश नीति की जानकारी रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञों हेतु आमतौर पर गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने हेतु जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री के स्थान पर उपराष्ट्रपति महोदय का जाना प्रतीकात्मक महत्व का था। इन विशेषज्ञों ने इसे भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन के एक प्रमुख तत्व के रूप में देखा, और कईयों ने तो यह कह दिया, कि अब गुटनिरपेक्षता का रहा-सहा महत्व भी खत्म हो चुका है। आज इस बहुध्रुवीय विश्व में अब बहुझुकाव (multialignment) अथवा बहुनिरपेक्षता की नीति का पालन कर रहा है।

तो क्या सच में भारत अपनी विदेश नीति में परिवर्तन कर चुका है? इस परिवर्तन के प्रमुख तत्व

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अथवा कारण क्या है? वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या है? और अंत में भविष्य की भारतीय विदेश नीति किस प्रकार हो – कि भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके? इन प्रश्नों के जवाब जानने से पूर्व थोड़ी चर्चा गुटनिरपेक्षता पर भी अवश्य कर लेनी चाहिए। तो आइये पहले जानते हैं, कि गुटनिरपेक्षता क्या है?

आजादी से पूर्व ही भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का पक्षधर था। चाहे आजादी से पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य हो, अथवा 1946 में औपनिवेशीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र में होने वाली घोषणा में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका, भारत हमेशा ही नव स्वतंत्र राष्ट्रों को नवउपनिवेशवाद से बचाने हेतु आगे बढ़ा रहा।

इसी पृष्ठभूमि में 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में नेहरू, टीटो तथा एनक्रूमा जैसे नेताओं ने गुटनिरपेक्षता की नींव रखी। इसमें नवस्वतंत्र राष्ट्रों को शीतयुद्धकालीन किसी गुट में शामिल

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

होने से रोकने, तथा सक्रिय मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाये रखने को प्रमुख उद्देश्य बनाया गया।

तात्कालिन परिस्थितियों में भारत जैसे नवस्वतंत्र राष्ट्र के लिये गुटनिरपेक्षता की यह नीति अत्यंत चुनौतिपूर्ण थी, पाकिस्तान, चीन जैसे अन्य देश जहां खुले-आम गुटों में शामिल हो रहे थे, वहीं भारत ने बहुत दबावों के बावजूद अपनी संप्रभुता से कोई समझौता न करते हुये, न केवल अपनी इस नीति पर कायम रहा बल्कि सक्रिय मध्यस्था निभाते हुये उत्तर कोरिया विवाद जैसे तनावपूर्ण मसलों पर दोनो शक्तियों (अमेरिका एवं रूस) के मध्य शांति बनाने में भी योगदान दिया।

तो आइये अब चलते है, अपने दूसरे प्रश्न कि क्या भारत सच में अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति में परिवर्तन कर चुका है? तथा इसके कारणों के बारे में जानते है।

तो जैसा की हम सभी जानते है, भारत ~~का~~ प्रारंभ से ही समाजवादी झुकाव के साथ मिश्रित

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अर्थव्यवस्था रहा है, तो इसे प्रारंभ से ही पश्चिमी देशों द्वारा साम्यवादी रूस के प्रति सहज झुकाव वाला माना जाता रहा है। इसके साथ ही 1971 तथा 1991 में हुयी दो घटनाओं ने भारतीय विदेश नीति को परिवर्तित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

आजादी के बाद पाकिस्तान से तात्कालिक कश्मीर विवाद हो, अथवा चीन द्वारा 1962 में किया गया एकतरफा आक्रमण, चारों तरफ से मंडराते इस सुरक्षा संबंधी खतरों ने भारत को अपने सीमायी हितों को सुरक्षित रखने हेतु रूस के साथ 1971 की "मित्रता संधि" करने पर मजबूर किया। हालांकि इस घटना को भी पश्चिमी विशेषज्ञों ने रूस के गुट में शामिल होने से देखा।

भारत तथा ~~रूस~~ रूस (तात्कालिक सोवियत संघ) के मध्य घनिष्ठ संबंध 1991 में घटित दो घटनाओं जिसमें प्रथम सोवियत संघ का विघटन अर्थात अब विश्व एकध्रुवीय हो चुका था। तथा दूसरी भारत की भुगतान संतुलन की

समस्या अर्थात अब भारत को संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था से बाहर निकलकर खुली अर्थव्यवस्था में प्रवेश करना था। अतः भारत की विदेश नीति को इन दोनों दबावों से सामंजस्य बैठाना पड़ा।

1991 के पश्चात कभी ~~कारगिल~~ 1998 में स्माईलिंग बुद्धा (परमाणु परीक्षण) तो कभी कारगिल युद्ध, कभी 2001 में रूस के साथ पारंपरिक मित्रता को आगे बढ़ाना हो, तो कभी आतंकवाद के मसले (2001 में ट्विन टावर हमले के बाद) पर अमेरिका से सहयोग हो भारतीय विदेश नीति लगातार तात्कालिन वास्तविकताओं के अनुरूप खुद को ढालती रही है।

~~अब~~ इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हुये अगर हम वर्तमान समय में युद्धनिरपेक्षता की प्रासंगिकता को देखेंगे तो यह पाते हैं कि-

अमेरिका अब प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी जिम्मेदारियों से हट रहा है। चाहे वो ईरान हो या उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान हो अथवा हिन्द-प्रशांत में अमेरिका की भूमिका

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

राष्ट्रपति ट्रंप की इन मुद्दो पर अनिश्चितता बनी है।

वहीं दूसरी ओर चीन आक्रामक तरीके से चाहे "वन बेल्ट वन रूट" हो अथवा हिन्द महासागर मे "मोतियों की माला" संबंधी उसकी भारत को घेरने की नीति हो, तथा चाहे वो डोकलाम विवाद हो अथवा पाकिस्तान को हर मुद्दे पर एकतरफा समर्थन हो, चीन हर जगह, हर वैश्विक मामले में अपनी आक्रामकता प्रदर्शित कर रहा है।

इन संदर्भों को ध्यान में रखते हुये भारत कि विदेश नीति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन स्पष्ट हुये हैं।

जहाँ एक तरफ हिन्द महासागर में सुरक्षा बढ़ाने हेतु अमेरिका के साथ LEMOA (लाजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ ~~आफ~~ एग्रीमेंट), फ्रांस के साथ उसके नौसेनिक अड्डों के प्रयोग संबंधी समझौता, "अमेरिका - जापान के साथ मालाबार" एक्सरसाइज, मिसाइल टेक्नालाजी कंट्रोल रिजीम, वासेनार, आस्ट्रेलिया समूह में प्रवेश तथा सुरक्षा परिषद में

प्रिक्षा हेतु सहयोग के कारण पाश्चिमी देशों से भारत के सामरिक संबंध मजबूत हुये है।

वही दूसरी तरफ विश्व-व्यापार संगठन (WTO) में पीस क्लाज, शंघाई सहयोग संगठन, डोकलाम-विवाद का शांतिपूर्ण निपटारा, RCEP जैसे मुद्दों तथा अर्न्तराष्ट्रीय नार्थ-साऊथ कारिडोर (INSTC), S-300 मिसाइल समझौता, ~~इंद्र~~ (नौसैनिक अभ्यास) के माध्यम से भारत--चीन एवं रूस के साथ सहयोग कर रहा है। इसीलिए -

उपरोक्त परिस्थितियों के कारण वर्तमान में गुटनिरपेक्षता की भूमिका सीमित अवश्य हुयी, तथा भारत को अब बहुनिरपेक्ष माना जाने लगा है

परंतु गुटनिरपेक्ष संगठन में 125 विकासशील एवं गरीब देशों का समूह भारत को नेतृत्व का अवसर प्रदान करता है, न केवल व्यापार संबंधी मामले बल्कि पर्यावरण, आतंकवाद तथा सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु भारत को गुटनिरपेक्ष संगठन की

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आवश्यकता है।

इसी प्रकार अंत की तरफ बढ़ते हुये अगर हम भविष्य की भारतीय विदेश नीति की दिशा के बारे में देखे तो - आतंकवाद, शरणार्थी संकट, चीन की आक्रामकता, पर्यावरणीय संकट तथा पेरिस समझौते से अमेरिका पीछे हटना, विकासशील अफ्रीकी देशों को आत्मनिर्भर बनाना, अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में भूमिका निभाने जैसी प्रमुख चुनौतियाँ भारत के सामने है।

अतः भारत को एक तरफ जहाँ जापान, अमेरिका, फ्रांस आदि लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कारिडोर, क्वाड, सामरिक तकनीकी का हस्तांतरण जैसे मुद्दों पर सहयोग करना चाहिए। वही दूसरी ओर चीन के साथ आर्थिक से आर्थिक पारस्परिक निर्भरता बढ़ाने, सीमाई विवाद समाधान, जलवायु के क्षेत्र की पारंपरिक मित्रता को नया आयाम देते हुये साझा हितो के मुद्दों पर सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार कदम उठाने से गुटनिरपेक्षता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

की प्रासंगिकता खत्म नहीं होगी, बल्कि वह नये कलेवर तथा नये स्वरूप में पूर्णतः भारतीय हितों पर आधारित पारस्परिक समानता एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित विदेश नीति को जन्म देगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Section B: परमाणु निरस्त्रीकरण समय की मांग है।

"संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा "परमाणु प्रतिषेध संधि" पारित" हाल ही में दुनिया के प्रमुख अखबारों में छपी इस खबर ने हमारा आकर्षित किया। फिर इसी के साथ ही एक बार फिर से परमाणु निरस्त्रीकरण की माँगों ने पुनः जोर पकड़ लिया। इससे संबंधित अन्य विषयों को खंगालने से कुछ प्रश्न अचानक ही मन में उठ खड़े हुये कि- परमाणु शस्त्रों को लेकर पूरा विश्व इतना चिंतित क्यों है? निरस्त्रीकरण के पक्ष तथा विपक्ष में किये जाने वाली प्रमुख तर्क-वितर्क क्या है? तथा भारत की परमाणु शस्त्रों संबंधी नीति एवं निरस्त्रीकरण किये जाने के संबंध में क्या विचार है? इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की - निरस्त्रीकरण हेतु क्या किया जाना चाहिए?

इन प्रश्नों पर विचार करने से पूर्व थोड़ा विचार परमाणु शस्त्रों के विकास पर कर लिया

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जाना चाहिए।

परमाणु हथियारों के विकास का आरंभ अमेरिकी वैज्ञानिक "ओपनहाइमर" के नेतृत्व में द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा तथा नागासाकी पर इस सर्वविनाशक बम के हमले ने पूरी दुनिया को इसके खतरनाक परिणामों का प्रथम बार दर्शन कराया।

द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के पश्चात पूँजीवाद – बनाम साम्यवाद की लड़ाई ने रूस को भी परमाणु बम बनाने हेतु प्रेरित किया, तथा देखते ही देखते रूस के पास इन हथियारों का भंडार इकट्ठा हो गया। इसी प्रकार तात्कालिन समय में विश्व शक्ति बनने की इच्छा रखने वाले देशों ने भी परमाणु अस्त्रों का विकास किया एवं रूस के बाद फ्रांस, ब्रिटेन तथा चीन ने भी इस सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया।

हालांकि भारत का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु 1948

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

में ही शुरू हो गया था, परंतु 1962 में चीन युद्ध तथा पाकिस्तान जैसे आक्रामक एवं गैर जिम्मेदार पड़ोसी से अपनी संप्रभुता की रक्षा करने हेतु परमाणु शस्त्र बनाने का विचार 70 के दशक में आया तथा भारत ने 1974 में अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया। 1998 में "स्माईलिंग बुद्ध" के बाद भारत ने भी अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न घोषित कर लिया।

इसके जवाब में चीन के सहयोग से पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के सहयोग से उत्तर कोरिया ने भी परमाणु शस्त्र बना लिये। इनके अतिरिक्त इजराइल ने भी परमाणु शस्त्रों का विकास किया है।

हालांकि ये विकास बिना कठिनाईयों के नहीं हुये, तथा परमाणु शस्त्रों के विकास के साथ ही इस पर प्रतिबंध लगाने की माँग को देखते हुये सुरक्षा परिषद् के पाँच सदस्य देशों (अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन) द्वारा परमाणु अप्रसार संधि (NPT)

Don't write anything this margin (कुछ भाग में कुछ ना लिखें)

तथा कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी (CTBT) बनी गयी, जिनका उद्देश्य परमाणु शस्त्रों की संख्या में कमी लाना, उनका प्रसार रोकना तथा जल, थल, वायु, एवं जमीन की गहराईयों में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाना था।

परंतु जैसा की हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इन संधियों में किये गये भेदभाव-पूर्ण प्रावधानों तथा शंकाओं ने अन्य देशों द्वारा परमाणु शस्त्रों के विकास को रोकने में सीमित सफलता ही प्राप्त की है।

तो आइये अब चलते हैं अपने प्रश्न की- विश्व परमाणु शस्त्रों को लेकर इतना चिंतित क्यों है? इसके जवाब में "इंटरनेशनल कैंपेन फॉर अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन (ICAN)" जिसे 2016 में शांति का नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, के द्वारा बताया गया तथ्य [redacted] वर्तमान में पूरे विश्व के पास लगभग 15000 परमाणु शस्त्र हैं। इसमें भी अमेरिका तथा रूस ने 3000 से अधिक शस्त्रों को उच्च अलर्ट पर रखा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर मिनटों में इसका प्रयोग किया जा सके।)

महत्वपूर्ण है। जब नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराये गये अपेक्षाकृत छोटे बमों (जिन्होंने तात्कालिन जापान का सर्वनाश तो किया ही, साथ ही इसके वर्तमान पीढ़ियों पर भी नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होते हैं।) ने सर्वनाश किया है, तो इन 3000 बमों के प्रभाव की तो कल्पना भी संभव नहीं है।

ब केवल ये देश बल्कि पाकिस्तान एवं उत्तर-कोरिया जैसे अलफल राष्ट्र भी परमाणु बमों का जखीरा रखते हैं। पाकिस्तान में सरकार में सेना एवं आतंकवादीयों की भूमिका के साथ-साथ इस क्षेत्र में बढ़ती हुयी ISIS की गतिविधियाँ पूरे विश्व हेतु संकट का विषय है। और यही बात उत्तर कोरिया की तो पूरा विश्व इस ही में तानाशाह किम जोंग-उन एवं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मध्य शब्दों के बाणों से चिंतित था, कि पता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

नहीं कब हमला हो जाये।

इसी प्रकार हमें अब परमाणु शस्त्रों को बनाये रखने एवं हटाये जाने संबंधी तर्क-वितर्क देख लेना चाहिए।

इसको बनाये रखने के पक्ष में कहा जाता है, कि इसने न केवल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति बनाये रखी है, बल्कि तकरारों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उत्तर कोरिया, तथा ईरान जैसे देश ईराक एवं अफगानिस्तान में पाश्चिमी शक्तियों द्वारा किये गये हस्तक्षेप से स्वंय की रक्षा करने हेतु इसे सही ठहराते है, वहीं भारत, चीन तथा पाकिस्तान से डिफेंस हेतु इसे बनाये रखने पर जोर देता है।

इसके अलावा पाश्चिमी देश परमाणु ऊर्जा अनुसंधान तथा अन्य क्षेत्रों यथा-कृषि, रोग (कैंसर) इत्यादि में इसके महत्व को ~~बढ़िया~~ देखते हुये भी इन्हें बने रहने देना चाहते है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हालांकि इन तर्कों के बावजूद इन मानवता के प्रति संकट को हटाने हेतु दिये गये तर्कों को देखने पर वे अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं।

हमने इसके विद्यमान संकट की तो चर्चा पूर्व में कर ही ली है, साथ ही परमाणु हथियार— हथियारों की होड़ को बढ़ावा देता है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में धन जिसे मानवीय विकास, गरीबों एवं वंचितों के कल्याण तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति में लगाया जाना चाहिए था, ऐसे हम विश्व को खतरे में डालने हेतु लगा रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए तो यह कीमत गरीबी, भुखमरी, सांप्रदायवाद, जातिवाद, बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र में दबाव, प्रादेशिक असमानता जैसी समस्याओं से मुँह-मोड़ लेने जैसी है।

एक अन्य तर्क जिसमें विवाद की स्थिति में पारंपरिक युद्धों में कम हानि होगी, जबकि परमाणवीय युद्ध के बाद भविष्य में विवाद हेतु यह "पृथ्वी ही नहीं बचेगी" का

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

दिया जाता है।

इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुये, तथा परमाणविक धमकियों की होड़ से स्वंय को अलग करने एवं सामाजिक कल्याण पर ध्यान देने हेतु भारत सरकार ने 2003 में "परमाणु डॉक्ट्रिन" जारी की, जिसमें "नो फर्स्ट यूज" अर्थात पहले हमला नहीं एवं धमकियों का प्रयोग पूरी क्षमता के साथ केवल बदला लेने हेतु किया जायेगा। जैसे प्रावधान शामिल किये। वर्तमान में अपने परमाणविक सिद्धान्त के कारण न केवल भारत एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। बल्कि अमेरिका, जापान एवं फ्रांस जैसे देशों के साथ NSG से परे हटकर असैन्य परमाणु समझौता तथा सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता हेतु इसकी मांग के समर्थन ने इसे मान्यता भी प्रदान की है।

इसी प्रकार अंत की

तरफ बढ़ते हुये हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, कि वर्तमान में कई विकसित देश, परमाणु तकनीक के दुष्प्रभावों को (फुकुशिमा, चेरनोबिल दुर्घटना) देखते हुये ऊर्जा के रूप में इसके प्रयोग से भी पांव पीछे खींच रहे हैं। हालांकि हथियारों के रूप में इसके निशस्त्रीकरण को लेकर व्यापक समझदारी का अभाव है। इसे दूर किये जाने हेतु ICAN जैसी संस्थाओं द्वारा, नागरिक समाज को इसकी हानियों के बारे में स्पष्ट करना चाहिए, तथा एकमत का निर्माण करके परमाणु हथियार रखने वाले देशों को वार्ता की मेज पर लाना चाहिए।

कांफ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जैसी पहलों को पुनर्जीवित करके ही पूरे विश्व के ऊपर से इस खतरनाक संकट को हटाया जाना समय की मांग है।